The Research Dialogue
An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed & Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X (Online)
Volume-03, Issue-01, April-2024
www.theresearchdialogue.com

स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम एवं युवा रोजगार: चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

वेद प्रकाश दुबे
असिस्टेंट प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्याल, जक्खिनी, वाराणसी।

सारांश

यह अध्ययन 31 दिसम्बर 2023 तक प्रकाशित आधिकारिक दस्तावेजों एवं अकादमिक साहित्य के आधार पर स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के संस्थागत विस्तार, युवा रोजगार की संभावनाओं तथा उससे जुड़ी चुनौतियों का समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। 2016 में प्रारम्भ हुई इस पहल ने नवाचार, वित्तीय सहायता, इन्क्यूबेशन, नियामकीय सरलीकरण और उद्यमिता की सार्वजनिक मान्यता को नीति के केन्द्र में रखा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिसम्बर 2023 में प्रकाशित वर्षान्त समीक्षा में 1.14 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और 12 लाख से अधिक स्व-रिपोर्टेड प्रत्यक्ष रोजगार का उल्लेख मिलता है। ये प्रशासनिक उपलब्धियाँ महत्वपूर्ण हैं, पर इनसे युवा आयु-वर्ग में शुद्ध अतिरिक्त रोजगार, वेतन, सामाजिक सुरक्षा या उद्यमों की उत्तरजीविता सिद्ध नहीं होती। शोध में वित्तीय पहुँच, कौशल, महानगर–जिला अंतर, महिला उद्यमिता और रोजगार गुणवत्ता के प्रश्नों को अलग-अलग परखा गया है। अध्ययन निष्कर्ष निकालता है कि कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन केवल मान्यता संख्या से नहीं, बल्कि सक्रिय उद्यम, टिकाऊ रोजगार, नवाचार की उपयोगिता और अवसरों के न्यायसंगत वितरण से होना चाहिए। इसके लिए जिला-स्तरीय सहायता, विश्वविद्यालय–उद्योग सहयोग, लक्षित वित्त और स्वतंत्र रोजगार निगरानी की अनुशंसा की गई है।

मुख्य शब्द: स्टार्टअप इंडिया; युवा रोजगार; उद्यमिता; नवाचार; वित्तीय समावेशन; कौशल विकास; क्षेत्रीय असमानता।

1. प्रस्तावना

भारत की जनसांख्यिकीय संरचना में युवाओं की बड़ी हिस्सेदारी आर्थिक विकास की संभावना के साथ रोजगार उपलब्ध कराने का दायित्व भी सामने रखती है। परंपरागत सरकारी नौकरी और संगठित क्षेत्र की सीमित अवशोषण क्षमता के बीच स्वरोजगार, सूक्ष्म उद्यम और नवाचार

आधारित उद्यमिता को नीतिगत महत्त्व मिला है। किंतु रोजगार की संख्या और रोजगार की गुणवत्ता में अंतर है। किसी नए उद्यम का स्थापित होना अपने आप में स्थायी, सामाजिक सुरक्षा युक्त और सम्मानजनक नौकरी का प्रमाण नहीं है। इसलिए स्टार्टअप इंडिया का आकलन उद्यम-संख्या, रोजगार, संस्थागत समर्थन तथा समावेशन के संयुक्त परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है।

16 जनवरी 2016 को प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया पहल का मूल उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, नियामकीय बाधाएँ घटाना, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण बनाना था। डीपीआईआईटी की मान्यता, कर-संबंधी प्रावधान, बौद्धिक संपदा सहायता, इन्क्यूबेशन और सरकारी खरीद में भागीदारी इसके प्रमुख घटक हैं। कार्यक्रम ने युवा स्नातकों के सामने नौकरी खोजने के अतिरिक्त नौकरी उत्पन्न करने का विचार भी रखा। यह बदलाव विशेषतः प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि-प्रौद्योगिकी और स्थानीय सेवाओं में दिखाई देता है।

इस नीति विमर्श में दो अतियों से बचना चाहिए। पहली, प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को सफल उद्यम मान लेना; दूसरी, स्टार्टअप क्षेत्र की संभावनाओं को इसलिए अस्वीकार करना कि सभी उद्यम सफल नहीं होते। स्टार्टअप का जोखिम उसकी प्रकृति का अंग है। सार्वजनिक नीति की भूमिका जोखिम को समाप्त करना नहीं, बल्कि उचित वित्त, जानकारी, संस्थागत सहयोग और बाजार तक पहुँच देकर उत्पादक प्रयोगों को संभव बनाना है। इस अध्ययन में इसी संतुलित दृष्टिकोण को अपनाया गया है।

2. अवधारणात्मक आधार एवं साहित्य समीक्षा

स्टार्टअप को सामान्य छोटे व्यवसाय से अलग समझने में नवाचार, पुनरावृत्त होने योग्य व्यवसाय मॉडल और विस्तार की संभावना महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। हालाँकि व्यवहार में उद्यमिता के कई रूप हैं: तकनीक-आधारित प्लेटफॉर्म, विनिर्माण इकाइयाँ, कृषि मूल्य-श्रृंखला, सामाजिक उद्यम और स्थानीय सेवाएँ। सभी की पूँजी, कौशल और रोजगार संरचना भिन्न होती है। इसलिए केवल एक समान नीति उपकरण से सभी उद्यमों की समस्याएँ हल नहीं की जा सकतीं।

शुम्पीटर (1934) ने उद्यमी को नए संयोजन और आर्थिक परिवर्तन से जोड़ा। इस दृष्टि से उद्यमिता केवल आत्मरोजगार नहीं, बल्कि नए उत्पाद, प्रक्रियाएँ, बाजार और संगठनात्मक रूपों का सृजन है। इसके विपरीत श्रम-अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण में रोजगार का महत्त्व उसकी स्थिरता, उत्पादकता, आय और सामाजिक सुरक्षा से निर्धारित होता है। दोनों विचारों को साथ रखने पर स्पष्ट होता है कि उद्यमिता-समर्थन तभी व्यापक सामाजिक उपलब्धि बनता है जब नवाचार का लाभ श्रमिकों, उपभोक्ताओं और स्थानीय समुदायों तक पहुँचे।

भारतीय संदर्भ में राष्ट्रीय कौशल विकास, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन और वित्तीय प्रौद्योगिकी ने उद्यम शुरू करने की लागत घटाने की संभावनाएँ बढ़ाई हैं। इसके साथ डिजिटल विभाजन, भाषाई बाधाएँ और परामर्श की असमान उपलब्धता बनी हुई हैं। किसी महानगर के तकनीकी स्नातक और छोटे जिले के प्रथम-पीढ़ी उद्यमी की जोखिम वहन करने की क्षमता समान नहीं होती। यह अंतर सार्वजनिक सहायता के लक्षित स्वरूप को आवश्यक बनाता है।

उपलब्ध सरकारी साहित्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और स्व-रिपोर्टेड प्रत्यक्ष रोजगार की श्रृंखला मिलती है; किंतु आयु-वार रोजगार, नौकरी की अवधि, औसत वेतन और उद्यम बंद होने की दर पर तुलनीय सार्वजनिक डेटा अपेक्षाकृत सीमित है। यही अंतर इस शोध की समस्या को निर्धारित करता है: क्या बढ़ती स्टार्टअप संख्या को युवा रोजगार की टिकाऊ उपलब्धि के रूप में पढ़ा जा सकता है?

3. शोध समस्या, उद्देश्य एवं प्रश्न

अध्ययन की केंद्रीय समस्या यह है कि स्टार्टअप इंडिया से जुड़े पंजीकरण और रोजगार संबंधी प्रमुख आँकड़े कार्यक्रम के विस्तार को तो दर्शाते हैं, पर युवाओं को मिले वास्तविक, गुणवत्तापूर्ण और दीर्घकालिक अवसरों का पूरा विवरण नहीं देते। रोजगार पर प्रभाव समझने के लिए कार्यक्रम की संरचना और उसके परिणामों के बीच संस्थागत मध्यस्थताओं की जाँच आवश्यक है।

शोध के उद्देश्य हैं: (क) स्टार्टअप इंडिया के प्रमुख घटकों का विवेचन; (ख) मान्यता प्राप्त स्टार्टअप तथा रिपोर्ट किए गए रोजगार की प्रवृत्तियों का विश्लेषण; (ग) युवा उद्यमियों की वित्तीय, कौशलगत और सामाजिक चुनौतियों की पहचान; (घ) क्षेत्रीय एवं लैंगिक समावेशन की समीक्षा; तथा (ङ) रोजगारोन्मुख नीति सुधारों का प्रस्ताव।

अध्ययन के प्रश्न हैं: कार्यक्रम के विस्तार और रोजगार के बीच किस प्रकार का वर्णनात्मक संबंध दिखाई देता है? सार्वजनिक सहायता के कौन-से साधन आरंभिक उद्यमों के लिए प्रासंगिक हैं? महानगरों से बाहर उद्यमिता का विस्तार किस प्रकार हो सकता है? और भविष्य में प्रभाव का मूल्यांकन किन बेहतर संकेतकों से किया जाना चाहिए?

4. शोध पद्धति एवं स्रोत

यह अध्ययन वर्णनात्मक, समीक्षात्मक तथा सीमित मात्रात्मक विश्लेषण पर आधारित है। इसके लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा जारी आधिकारिक विवरण, संसद में प्रस्तुत लिखित उत्तर, स्टार्टअप इंडिया से संबंधित सरकारी दस्तावेज तथा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के निष्कर्ष लिए गए हैं। मूल डेटा संग्रह, प्रश्नावली, साक्षात्कार या प्रतिगमन मॉडल का दावा नहीं किया गया है। अध्ययन की समय-सीमा 31 दिसम्बर 2023 है। इसमें 2023 तक प्रकाशित सरकारी प्रेस विज्ञप्तियाँ, स्टार्टअप इंडिया कार्ययोजना, 2022–23 तक उपलब्ध श्रम बाजार रिपोर्ट तथा शास्त्रीय उद्यमिता साहित्य का विवेचन किया गया है। बाद में प्रकाशित स्रोतों से प्राप्त पश्चदृष्टि आँकड़ों को जानबूझकर शामिल नहीं किया गया है।

सीमाएँ स्पष्ट हैं। स्टार्टअप द्वारा सूचित प्रत्यक्ष नौकरियों में युवाओं की आयु-वार हिस्सेदारी उपलब्ध नहीं है। किसी उद्यम के रोजगार का अनुमान उसके सभी कर्मचारियों को नई राष्ट्रीय नौकरियाँ मानकर नहीं लगाया जा सकता। रिपोर्ट किए गए रोजगार में उद्यम बंद होने, कर्मचारियों के स्थानांतरण और रोजगार की गुणवत्ता का पूर्ण समायोजन नहीं है। इस कारण अध्ययन के निष्कर्ष नीति-व्याख्यात्मक हैं, न कि प्रयोगात्मक कारण-प्रभाव संबंधी।

5. स्टार्टअप इंडिया: नीति संरचना एवं संस्थागत समर्थन

स्टार्टअप इंडिया की संस्थागत व्यवस्था कई स्तरों पर काम करती है। डीपीआईआईटी मान्यता उद्यम को औपचारिक पहचान देती है; इन्क्यूबेटर विचार को उत्पाद में बदलने में मार्गदर्शन करते हैं; वित्तीय साधन आरंभिक प्रयोग और विस्तार के लिए संसाधन उपलब्ध कराते हैं; तथा बाजार तक पहुँच उद्यम को राजस्व अर्जित करने में सहायता करती है। इन चरणों के बीच समन्वय कमजोर हो तो पंजीकरण के बाद भी उद्यम स्थिर नहीं हो पाता।

फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (FFS) के अंतर्गत सार्वजनिक पूँजी सीधे प्रत्येक उद्यम को नहीं दी जाती; यह सिडबी के माध्यम से वैकल्पिक निवेश कोषों तक पहुँचती है, जो आगे पात्र स्टार्टअप में निवेश करते हैं। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) विचार-

सत्यापन, प्रोटोटाइप और प्रारंभिक व्यावसायीकरण के लिए इन्क्यूबेटरों के माध्यम से सहायता देती है। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (CGSS) ऋणदाताओं के जोखिम को कम करने का एक अलग उपाय है।

सरकारी खरीद में भागीदारी, बौद्धिक संपदा सहायता और परामर्श सेवाएँ वित्तीय योजनाओं जितनी ही महत्त्वपूर्ण हैं। उद्यमी को उत्पाद विकसित करने के साथ ग्राहकों, अनुपालन, कर, अनुबंध और कर्मचारियों के प्रबंधन की समझ चाहिए। युवा उद्यमियों के लिए यह व्यावहारिक ज्ञान अक्सर औपचारिक शिक्षा से बाहर रह जाता है। इसलिए उद्यमिता शिक्षा को वास्तविक बाजार अनुभव से जोड़ना आवश्यक है।

तालिका 1. प्रमुख वित्तीय सहायता तंत्र

योजना	सहायता का स्वरूप	लक्षित चरण / प्रमुख सीमा
Fund of Funds for Startups (FFS)	SIDBI के माध्यम से AIF में प्रतिबद्ध पूँजी; AIF पात्र स्टार्टअप में निवेश करते हैं	वृद्धि/विस्तार; स्टार्टअप को प्रत्यक्ष सरकारी अनुदान नहीं
Startup India Seed Fund Scheme (SISFS)	चयनित इन्क्यूबेटरों के माध्यम से प्रारंभिक सहायता	अवधारणा प्रमाण, प्रोटोटाइप, उत्पाद परीक्षण एवं बाजार प्रवेश
Credit Guarantee Scheme for Startups (CGSS)	पात्र ऋणदाताओं को ऋण के लिए गारंटी समर्थन	ऋण पहुँच; गारंटी को प्रत्यक्ष नकद अनुदान न समझें

स्रोत: DPIIT (2016); वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (2023)। योजना की पात्रता एवं प्रावधान संबंधित दिशानिर्देशों के अधीन हैं।

6. आँकड़ों का विश्लेषण: विस्तार और रोजगार

दिसम्बर 2023 में प्रकाशित डीपीआईआईटी की वर्षान्त समीक्षा के अनुसार देश में 1.14 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप थे और उनसे 12 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार रिपोर्ट किए गए थे। दिसम्बर 2022 के आधिकारिक वक्तव्य में 30 नवम्बर 2022 तक 8.6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार दर्ज थे। इन दोनों प्रकाशनों के बीच का अंतर रिपोर्टिंग तिथि और संचयी दायरे से प्रभावित है; इसे किसी एक वर्ष में उत्पन्न शुद्ध रोजगार के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 2022, 2023)।

2023 की वर्षान्त समीक्षा में फंड ऑफ फंड्स योजना के अंतर्गत लगभग ₹10,229 करोड़ की प्रतिबद्धता, 129 वैकल्पिक निवेश कोष तथा इन कोषों द्वारा 915 स्टार्टअप में ₹17,272 करोड़ निवेश का विवरण दिया गया। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में 192 इन्क्यूबेटरों के लिए ₹747 करोड़ की स्वीकृति का भी उल्लेख है। ये विभिन्न वित्तीय अवधारणाएँ हैं: प्रतिबद्धता, निवेश और स्वीकृति को एक-दूसरे के पर्याय नहीं माना जा सकता।

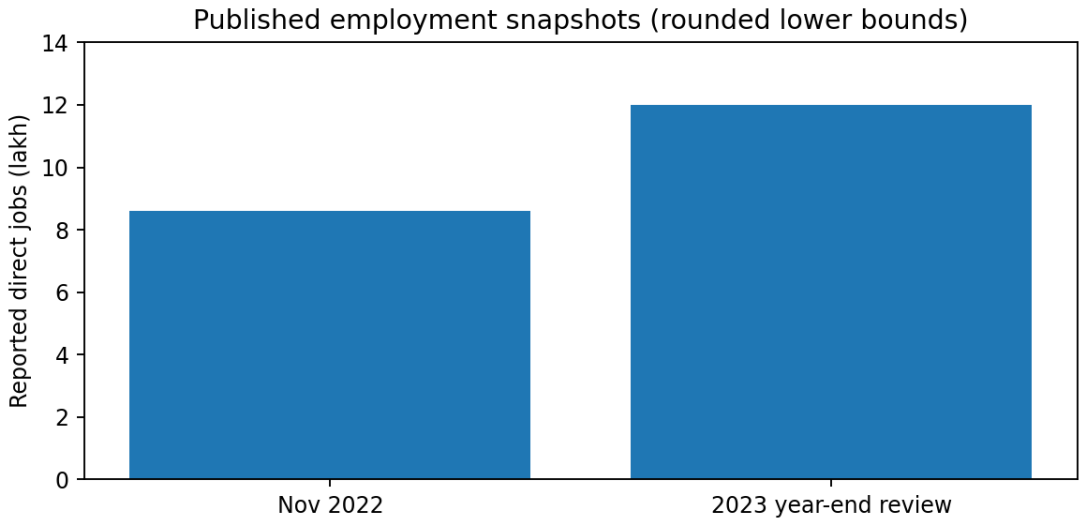
तालिका 2. वर्ष 2023 तक प्रकाशित चयनित आधिकारिक संकेतक

संकेतक	प्रकाशित स्थिति	स्रोत/तिथि
मान्यता प्राप्त स्टार्टअप	1.14 लाख से अधिक	DPIIT वर्षान्त समीक्षा, दिसम्बर 2023
रिपोर्टेड प्रत्यक्ष रोजगार	12 लाख से अधिक	DPIIT वर्षान्त समीक्षा, दिसम्बर 2023

प्रत्यक्ष रोजगार	8.6 लाख से अधिक	PIB, 16 दिसम्बर 2022; 30 नवम्बर तक
FFS के अंतर्गत AIF को प्रतिबद्धता	लगभग ₹10,229 करोड़	DPIIT वर्षान्त समीक्षा, 2023
AIF द्वारा निवेश	₹17,272 करोड़; 915 स्टार्टअप	DPIIT वर्षान्त समीक्षा, 2023
SISFS स्वीकृतियाँ	₹747 करोड़; 192 इन्क्यूबेटर	DPIIT वर्षान्त समीक्षा, 2023

टिप्पणी: संख्याएँ संबंधित प्रकाशनों में प्रयुक्त गोलाई के साथ दी गई हैं; रोजगार स्व-रिपोर्टेड है।

चित्र 1. प्रकाशित रोजगार संकेतकों की तुलना



स्रोत: PIB (2022) एवं DPIIT वर्षान्त समीक्षा (2023)। दोनों मान न्यूनतम गोल संख्या हैं, स्वतंत्र वार्षिक प्रवाह नहीं।

चित्र 2. उद्यमिता से गुणवत्तापूर्ण रोजगार तक प्रस्तावित प्रक्रिया

7. युवा रोजगार: अवसरों का स्वरूप

स्टार्टअप अर्थव्यवस्था युवाओं को तीन तरह के अवसर देती है। पहला, संस्थापक या सह-संस्थापक के रूप में उद्यम स्थापित करना; दूसरा, नए उद्यमों में वेतनभोगी रोजगार प्राप्त करना; तीसरा, स्वतंत्र पेशेवर, आपूर्तिकर्ता, प्रशिक्षक और स्थानीय सेवा प्रदाता के रूप में अप्रत्यक्ष आर्थिक अवसर अर्जित करना। सरकारी प्रत्यक्ष रोजगार का आँकड़ा इन सभी श्रेणियों का समग्र माप नहीं है। विशेष रूप से गिग कार्य और अनुबंध आधारित सेवाओं को समझने के लिए अलग विश्लेषण चाहिए।

तकनीकी स्टार्टअप सॉफ्टवेयर विकास, डेटा विश्लेषण, उत्पाद प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और डिजिटल विपणन में अवसर देते हैं। दूसरी ओर कृषि-प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और स्थानीय विनिर्माण विविध शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं को जोड़ सकते हैं। रोजगार नीति के लिए यह विविधता महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि सभी युवा उच्चस्तरीय कोडिंग कौशल नहीं रखते।

युवा बेरोजगारी के लिए 15–29 वर्ष की आयु-समूह पर आधारित PLFS 2022–23 की आयु-विशिष्ट तालिकाएँ प्रासंगिक हैं; इन्हें 15 वर्ष और उससे अधिक की समग्र बेरोजगारी दर से नहीं मिलाना चाहिए। इस अध्ययन में स्टार्टअप-विशिष्ट आयु-वार नियुक्ति डेटा उपलब्ध न होने के कारण प्रत्यक्ष रोजगार को समस्त युवा रोजगार नहीं माना गया है।

8. प्रमुख चुनौतियाँ

वित्तीय पहुँच की समस्या सर्वाधिक चर्चित है। प्रारंभिक चरण में उद्यम के पास संपार्श्विक, विश्वसनीय नकदी प्रवाह और लंबे कारोबारी इतिहास का अभाव होता है। निवेशक प्रायः तेजी से बढ़ सकने वाले मॉडल को प्राथमिकता देते हैं, जबकि छोटे शहरों के सामाजिक, कृषि या विनिर्माण उद्यमों को अपेक्षाकृत धैर्यपूर्ण पूँजी चाहिए। सहायता योजनाओं की उपलब्धता और उनके बारे में सही जानकारी के बीच अंतर भी कई संभावित उद्यमियों को पीछे रखता है।

कौशल संबंधी चुनौती केवल तकनीकी प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है। बाजार अनुसंधान, लेखांकन, अनुबंध, बौद्धिक संपदा, टीम नेतृत्व, गुणवत्ता नियंत्रण और ग्राहक सेवा जैसे कौशल आवश्यक हैं। शिक्षा संस्थानों में उद्यमिता विषय पढ़ाए जाने के बावजूद वास्तविक समस्या-समाधान, उत्पाद परीक्षण और विफलता से सीखने के अवसर सीमित हो सकते हैं। उद्यमिता प्रशिक्षण को प्रमाणपत्र-आधारित गतिविधि से आगे ले जाकर व्यवहारिक अनुभव बनाना होगा।

क्षेत्रीय असमानता एक अन्य चुनौती है। बड़े शहरों में निवेशक, अनुभवी मार्गदर्शक, डिजिटल नेटवर्क और उच्च-आय वाले ग्राहक अधिक सुलभ होते हैं। छोटे जिलों में प्रतिभा होते हुए भी परीक्षण प्रयोगशाला, उत्पाद डिज़ाइन सहायता और संस्थागत संपर्क की कमी हो सकती है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी जिला-वार परिस्थितियाँ समान नहीं हैं। राज्य स्तर पर स्टार्टअप संख्या बढ़ना अपने आप में प्रत्येक जिले में संतुलित अवसरों की गारंटी नहीं देता।

2023 तक प्रकाशित प्रशासनिक दस्तावेज महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए विविध योजनाओं का उल्लेख करते हैं। तथापि किसी स्टार्टअप में महिला निदेशक होने का अर्थ यह नहीं कि उद्यम की संस्थापक, बहुसंख्यक स्वामी या वास्तविक निर्णयकर्ता महिला ही हो। इन भूमिकाओं का पृथक मापन आवश्यक है।

रोजगार की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। तेजी से विस्तार करने वाले उद्यमों में काम की गति, नौकरी की अनिश्चितता और प्रदर्शन का दबाव अधिक हो सकता है। दूसरी ओर लचीले काम, सीखने के अवसर और नए कौशल प्राप्त करने की संभावना भी होती है। नीति मूल्यांकन में नियुक्ति-पत्र, वेतन, कार्य-घंटे, लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा और कौशल प्रगति जैसे संकेतक सम्मिलित होने चाहिए।

अंततः नियामकीय अनुपालन और बाजार में प्रतिस्पर्धा से जुड़े जोखिम हैं। नए उद्यमों को अनेक प्रक्रियाएँ समझनी पड़ती हैं। बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्मों की बाजार शक्ति, ग्राहक अधिग्रहण की लागत और समय पर भुगतान न मिलना छोटे उद्यमों की स्थिरता प्रभावित कर सकता है। सहायता का उद्देश्य केवल कंपनी खोलना नहीं, बल्कि उसे पारदर्शी और उत्तरदायी तरीके से चलने योग्य बनाना होना चाहिए।

9. संभावनाएँ एवं उभरते क्षेत्र

भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था, सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना और स्मार्टफोन आधारित सेवाएँ कम लागत पर बाजार तक पहुँच के अवसर पैदा करती हैं। हालांकि डिजिटल सुविधा तभी समावेशी बनेगी जब भाषा, साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता पर समान निवेश हो। भारतीय भाषाओं में उद्यमिता मार्गदर्शन, स्थानीय ग्राहक सहायता और सस्ती तकनीकी सेवाएँ छोटे शहरों में नवाचार को बढ़ा सकती हैं।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रसंस्करण, भंडारण, आपूर्ति-श्रृंखला, जल प्रबंधन, कृषि परामर्श और स्थानीय उत्पादों के ब्रांड निर्माण की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। ऐसे उद्यम महानगरीय तकनीकी मॉडल से अलग पूँजी तथा बाजार सहायता माँगते हैं। जिला उद्योग केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, किसान उत्पादक संगठन और इन्क्यूबेटर का सहयोग युवाओं को स्थानीय समस्याओं से जुड़े व्यावसायिक समाधान विकसित करने में मदद कर सकता है।

हरित अर्थव्यवस्था में ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, पुनर्चक्रण, जल संरक्षण और स्वच्छ परिवहन से जुड़े नए व्यवसाय उभर सकते हैं। इन क्षेत्रों में रोजगार की मात्रा से अधिक उसकी उपयोगिता और पर्यावरणीय प्रभाव भी महत्त्वपूर्ण है। सरकारी खरीद तथा स्थानीय निकायों की समस्याओं को नवाचार प्रतियोगिताओं से जोड़ने पर मांग आधारित उद्यमिता को बढ़ावा मिल सकता है।

उच्च शिक्षा संस्थान स्टार्टअप पारिस्थितिकी के महत्त्वपूर्ण प्रवेश-द्वार बन सकते हैं। विश्वविद्यालयों में केवल प्रतियोगिता और व्याख्यान के बजाय समस्या पहचान, उद्योग परामर्श, प्रोटोटाइप अनुदान, विधिक सहायता और पूर्व विद्यार्थियों का मार्गदर्शन एकीकृत होना चाहिए। स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए उद्यमिता को सभी विषयों में लागू करने योग्य क्षमता के रूप में विकसित किया जा सकता है।

10. नीतिगत सुझाव

पहला सुझाव रोजगार-केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली विकसित करना है। डीपीआईआईटी मान्यता के साथ सक्रियता, बंद होने की स्थिति, कर्मचारी संख्या, आयु-वार भर्ती, वेतन बैंड और नौकरी टिकाव का गोपनीयता-सम्मत अनुवर्ती सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इससे नीति निर्माता सकल पंजीकरण से आगे बढ़कर वास्तविक आर्थिक योगदान को समझ सकेंगे। स्वतंत्र मूल्यांकन और स्पष्ट परिभाषाएँ सरकारी दावों की विश्वसनीयता बढ़ाएँगी।

दूसरा, जिला-स्तरीय उद्यमिता सहायता केंद्रों को विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, आईटीआई और स्थानीय उद्योग के साथ जोड़ा जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में एक ही प्रकार के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के बजाय स्थानीय संसाधन, बाजार और कौशल के अनुसार क्षेत्र चुने जाएँ। उत्पाद-परीक्षण, साझा मशीनरी, कानूनी परामर्श और डिजिटल विपणन के लिए सामूहिक सुविधाएँ लागत कम कर सकती हैं।

तीसरा, वित्तीय सहायता को उद्यम के जीवन-चक्र से जोड़ना चाहिए। विचार चरण में छोटे अनुदान और मार्गदर्शन, प्रारंभिक बिक्री पर कार्यशील पूँजी, तथा विस्तार पर उपयुक्त ऋण या इक्विटी सहायता अधिक प्रभावी हो सकती है। चयन प्रक्रियाओं में स्पष्ट मानदंड, समयबद्ध निर्णय और शिकायत निवारण व्यवस्था होनी चाहिए। महिला तथा प्रथम-पीढ़ी उद्यमियों के लिए लक्षित मेंटरशिप और नेटवर्क सहयोग उपयोगी होगा।

चौथा, कौशल विकास को वास्तविक उद्योग समस्याओं के साथ एकीकृत किया जाए। विद्यार्थियों को ग्राहक साक्षात्कार, बाजार सर्वेक्षण, लागत गणना, डिजिटल सुरक्षा और रोजगार कानून का व्यावहारिक अनुभव मिले। केवल सफल संस्थापकों की कहानियों के बजाय असफल प्रयोगों से मिली सीख को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए। इससे उद्यमिता के प्रति यथार्थवादी दृष्टि विकसित होगी।

पाँचवाँ, सरकारी खरीद और निजी बाजार से जुड़ाव बढ़ाया जाए। उत्पादों के लिए मानकीकरण, गुणवत्ता परीक्षण, समयबद्ध भुगतान तथा स्थानीय खरीद की पारदर्शी प्रक्रियाएँ स्टार्टअप के राजस्व जोखिम को घटा सकती हैं। निवेश जुटाना अपने आप में व्यावसायिक सफलता नहीं है; नियमित ग्राहक और टिकाऊ आय अधिक ठोस संकेतक हैं।

छठा, समावेशी उद्यमिता के लिए महिला, ग्रामीण, वंचित समुदायों और गैर-अंग्रेजी भाषी युवाओं की बाधाओं को अलग-अलग समझना आवश्यक है। प्रशिक्षण सामग्री का स्थानीय भाषाओं में विकास, सुलभ डिजिटल मंच, परिवहन और देखभाल-संबंधी सहायता तथा सुरक्षित कार्य वातावरण अधिक व्यापक सहभागिता को संभव बना सकते हैं।

11. चर्चा: उपलब्धियों और दावों के बीच संतुलन

उपलब्ध आँकड़े बताते हैं कि स्टार्टअप इंडिया ने औपचारिक मान्यता और नवाचार आधारित उद्यमिता के विस्तार में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाला नीतिगत ढाँचा विकसित किया है। सरकारी सहायता के विविध साधन यह स्वीकार करते हैं कि उद्यम की जरूरतें विचार से लेकर विस्तार तक बदलती रहती हैं। फिर भी कार्यक्रम के प्रभाव को केवल संचयी संख्याओं से सिद्ध करना शोध की दृष्टि से अपर्याप्त होगा। यहाँ कारणात्मकता और सह-संबंध का अंतर केंद्रीय है। किसी अवधि में स्टार्टअप संख्या बढ़ने के साथ रोजगार बढ़ना वर्णनात्मक संबंध है। पर यह स्थापित करने के लिए कि कितनी नौकरियाँ कार्यक्रम के बिना नहीं बनतीं, तुलनात्मक समूह, उद्यम स्तर पर समय-श्रृंखला, नीति पात्रता में अंतर और बाहरी आर्थिक परिस्थितियों का नियंत्रित अध्ययन चाहिए। कोविड-19, डिजिटल परिवर्तन, निजी निवेश और राज्य सरकारों की नीतियाँ भी परिणामों को प्रभावित करती हैं।

युवा रोजगार का प्रश्न केवल उद्यम खोलने से हल नहीं होता। शिक्षा से काम तक संक्रमण, कौशल मिलान, स्थानिक गतिशीलता और श्रम की गरिमा उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं। उद्यमिता का आदर्श रोजगार की समूची जिम्मेदारी युवाओं पर डालने का साधन नहीं बनना चाहिए। मजबूत सार्वजनिक शिक्षा, अवसंरचना और सामाजिक सुरक्षा के साथ उद्यमिता एक पूरक विकास-पथ बन सकती है।

12. निष्कर्ष

2016 से 2023 तक की उपलब्ध सूचनाएँ यह दर्शाती हैं कि स्टार्टअप इंडिया ने नवाचार-आधारित उद्यमिता को संस्थागत पहचान देने, निवेश-समर्थन के माध्यम विकसित करने तथा नए व्यवसायों को सार्वजनिक नीति से जोड़ने में उल्लेखनीय प्रगति की। फिर भी मान्यता प्राप्त उद्यमों की संख्या को रोजगार की स्थायित्वपूर्ण उपलब्धि के बराबर रखना उचित नहीं है। प्रत्यक्ष रोजगार के प्रकाशित संकेतक मुख्यतः स्व-रिपोर्टेड हैं; उनके आयु-वार वितरण, कार्य की अवधि और वेतन गुणवत्ता की स्वतंत्र पुष्टि इस अध्ययन में उपलब्ध नहीं है। अतः निष्कर्ष कार्यक्रम की संभावनाओं और संस्थागत सीमाओं पर केन्द्रित हैं, न कि उसके शुद्ध कारणात्मक प्रभाव पर।

13. रोजगार मापन की व्यावहारिक जटिलताएँ

रोजगार संबंधी आँकड़ों का उपयोग करते समय सर्वप्रथम गणना की इकाई समझनी चाहिए। एक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप किसी विशेष तिथि पर सक्रिय हो सकता है, बाद में बंद हो सकता है अथवा उसका विलय किसी दूसरे उद्यम में हो सकता है। इसी प्रकार किसी कर्मचारी का एक उद्यम छोड़कर दूसरे में जाना दोनों कंपनियों की भर्ती के आँकड़ों में अलग-अलग दर्ज हो सकता है। इसलिए सकल रिपोर्टेड रोजगार को एक निश्चित समय पर मौजूद रोजगार-स्टॉक से अलग समझना जरूरी है। विश्वसनीय निगरानी व्यवस्था में नियुक्तियों के साथ नौकरी छोड़ने, बंद हुए उद्यमों और रोजगार की अवधि का भी रिकॉर्ड होना चाहिए।

युवा रोजगार की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों में युवा आयु-समूह अलग-अलग हो सकते हैं। यदि स्टार्टअप के सभी कर्मचारियों को युवा मान लिया जाए तो वास्तविक हिस्सेदारी का अतिशयोक्तिपूर्ण अनुमान बनेगा। बेहतर अध्ययन में

कर्मचारियों को 15–29 वर्ष, 30–44 वर्ष और अन्य आयु-वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रथम रोजगार, पुनर्नियोजन, इंटर्नशिप और स्व-नियोजित संस्थापक को अलग-अलग श्रेणियों में रखना चाहिए।

रोजगार की गुणवत्ता का एक उपयोगी संकेतक नियमित आय है। किसी युवा को नौकरी मिलने के बावजूद यदि भुगतान अनियमित हो, अनुबंध अस्पष्ट हो या कौशल प्रगति न हो, तो रोजगार का सामाजिक लाभ सीमित रह सकता है। इसीलिए भविष्य के सर्वेक्षणों में औसत वेतन के साथ वेतन-वितरण, कार्य-घंटे, प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा का मापन जरूरी है। इससे स्टार्टअप क्षेत्र की तुलना अन्य औपचारिक और अनौपचारिक रोजगार क्षेत्रों से अधिक अर्थपूर्ण ढंग से की जा सकेगी।

14. ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी भारत के लिए विशेष रणनीति

ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी भारत में उद्यमिता को केवल महानगरीय डिजिटल कंपनियों की प्रतिकृति बनाकर विकसित नहीं किया जा सकता। वहाँ कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, स्थानीय हस्तशिल्प, मरम्मत सेवाएँ, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा से जुड़ी समस्याएँ उद्यमिता के अवसर बन सकती हैं। ऐसे उद्यमों को ग्राहक तक पहुँच, उत्पाद गुणवत्ता, भंडारण, परिवहन और स्थानीय भाषा में व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता अधिक होती है। इसलिए एक जिला–एक समाधान जैसी समस्या-केंद्रित पहल उपयोगी हो सकती है, बशर्ते उसका चयन स्थानीय माँग के वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर आधारित हो।

ग्रामीण युवाओं के सामने प्रारंभिक पूँजी के अतिरिक्त बाजार की अनिश्चितता बड़ी बाधा है। कोई युवा स्थानीय उत्पाद तैयार कर भी ले, तो बड़े खरीदार तक पहुँच और समय पर भुगतान न मिलने से व्यवसाय रुक सकता है। सहकारी संस्थाओं, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों तथा डिजिटल व्यापार मंचों से साझेदारी इस जोखिम को कुछ सीमा तक कम कर सकती है। फिर भी प्रत्येक सहयोग मॉडल के लिए उत्तरदायित्व, गुणवत्ता और लाभ के न्यायसंगत वितरण की स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक होगी।

अर्द्धशहरी महाविद्यालयों में उद्यमिता प्रकोष्ठ स्थापित करने से स्थानीय ज्ञान और औपचारिक शिक्षा के बीच संवाद बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए विज्ञान के विद्यार्थी खाद्य संरक्षण की तकनीक विकसित करें, वाणिज्य के विद्यार्थी लागत और विपणन मॉडल तैयार करें तथा सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी उपभोक्ता आवश्यकताओं का अध्ययन करें। ऐसी बहुविषयी गतिविधि छात्रों को उद्यमिता का अनुभव देती है और केवल सैद्धांतिक पाठ्यक्रम की सीमा से बाहर ले जाती है।

15. शिक्षा, नवाचार और संस्थागत साझेदारी

उच्च शिक्षा में उद्यमिता के लिए केवल प्रेरक भाषण पर्याप्त नहीं हैं। संस्थानों को ऐसे संरचित अवसर देने चाहिए जिनमें छात्र वास्तविक समस्या चुनें, संभावित उपभोक्ताओं से बातचीत करें, उत्पाद या सेवा का सीमित परीक्षण करें और प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर सुधार करें। इन गतिविधियों में व्यावसायिक नैतिकता, डेटा गोपनीयता, उपभोक्ता अधिकार और श्रम संबंधी उत्तरदायित्व भी शामिल किए जाने चाहिए। उद्यमिता को शिक्षा से जोड़ने का अर्थ केवल निजी व्यवसाय स्थापित करना नहीं, बल्कि समस्या-समाधान और सहयोग की क्षमता विकसित करना है।

विश्वविद्यालय–उद्योग सहयोग की सफलता औपचारिक समझौता ज्ञापन की संख्या से नहीं मापी जानी चाहिए। अधिक सार्थक संकेतक संयुक्त परियोजनाएँ, उद्योग विशेषज्ञों द्वारा वास्तविक मार्गदर्शन, परीक्षण सुविधाओं का उपयोग, छात्र इंटर्नशिप और बाजार में पहुँचने वाले

उत्पाद हैं। शिक्षकों को भी उद्यमिता परामर्श और तकनीक हस्तांतरण के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण तथा संस्थागत प्रोत्साहन मिलना चाहिए। छोटे महाविद्यालयों के लिए साझा क्षेत्रीय इन्क्यूबेशन केंद्र लागत प्रभावी विकल्प हो सकते हैं।

शिक्षा संस्थानों में उद्यमिता का मूल्यांकन करते समय असफल प्रयासों को पूरी तरह नकारात्मक परिणाम नहीं मानना चाहिए। यदि छात्र ने ग्राहक की जरूरत पहचानी, लागत का सही अनुमान लगाया और प्रयोग से सीख हासिल की, तो वह अनुभव भविष्य के रोजगार में भी उपयोगी है। इस प्रकार उद्यमिता शिक्षा का लाभ केवल नए पंजीकृत स्टार्टअप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि रोजगार-योग्यता, संवाद कौशल और निर्णय क्षमता के विकास तक फैलता है।

16. समावेशन एवं उत्तरदायी उद्यमिता

उद्यमिता की सफलता का सामाजिक मूल्यांकन तभी संतुलित होगा जब विभिन्न सामाजिक समूहों की वास्तविक भागीदारी पर ध्यान दिया जाए। महिला निदेशक या भागीदार की उपस्थिति एक प्रारंभिक संकेतक है, पर यह जरूरी नहीं कि वह उद्यम की संस्थापक, प्रमुख निवेशक अथवा निर्णय लेने वाली व्यक्ति भी हो। इस अंतर को स्पष्ट किए बिना महिला नेतृत्व के बारे में बड़े निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। भविष्य के डेटा में स्वामित्व, प्रबंधन, निवेश और रोजगार की श्रेणियों को अलग-अलग प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

दिव्यांग युवाओं, प्रथम-पीढ़ी शिक्षार्थियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए उद्यमिता प्रशिक्षण की लागत भी बाधा बन सकती है। डिजिटल मंचों की सुलभता, स्थानीय भाषा में सामग्री, छोटे प्रारंभिक अनुदान और व्यक्तिगत मार्गदर्शन समावेशन को बढ़ा सकते हैं। परंतु सहायता का मूल्यांकन केवल प्रशिक्षण में भाग लेने वालों की संख्या से नहीं, बल्कि प्रशिक्षण के बाद वास्तविक उद्यम या रोजगार परिणाम से किया जाना चाहिए।

उत्तरदायी उद्यमिता का अर्थ पर्यावरण, श्रमिकों, उपभोक्ताओं और स्थानीय समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व भी है। नवाचार का उद्देश्य केवल तेज वित्तीय वृद्धि नहीं होना चाहिए। यदि उद्यम रोजगार उत्पन्न करे किंतु श्रमिक सुरक्षा की अनदेखी करे या संसाधनों का अस्थिर उपयोग करे, तो उसका दीर्घकालिक सामाजिक योगदान संदिग्ध रहेगा। टिकाऊ विकास के लिए उद्यमों को शुरुआत से ही पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के मानक अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

संदर्भ सूची :

- Department for Promotion of Industry and Internal Trade. (2016). Startup India: Action plan. Government of India. https://www.startupindia.gov.in/
- Ministry of Commerce and Industry. (2022, December 16). Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) recognized startups create over 8.6 lakh direct jobs since the launch of Startup India. Press Information Bureau. https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1884256

- Ministry of Commerce and Industry. (2023). 2023 year end review for Department for Promotion of Industry and Internal Trade. Press Information Bureau. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1990377
- Ministry of Commerce and Industry. (2023). Promotion of startups [Parliamentary information on the Credit Guarantee Scheme for Startups]. Press Information Bureau. https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1945152
- Ministry of Statistics and Programme Implementation. (2023). Periodic Labour Force Survey (PLFS): Annual report, July 2022–June 2023. Government of India.
- Ministry of Commerce and Industry. (2022). Promotion of startups [Sector-wise recognised startups as of March 28, 2022]. Press Information Bureau. https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1814146
- Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle. Harvard University Press.
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। (2022)। युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार रुझान 2022: युवाओं के भविष्य को बदलने के लिए निवेश। ILO। https://www.ilo.org/
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। (2023)। विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण: रुझान 2023। ILO। https://www.ilo.org/
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)। (2017)। द मिसिंग एंटरप्रेन्योर्स 2017: समावेशी उद्यमिता के लिए नीतियां। OECD पब्लिशिंग। https://doi.org/10.1787/9789264283602-en
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)। (2023)। OECD SME और उद्यमिता दृष्टिकोण 2023। OECD पब्लिशिंग। https://doi.org/10.1787/342b8564-en
- विश्व बैंक। (2020)। डूइंग बिजनेस 2020। विश्व बैंक। https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1440-2
- भारत सरकार। (2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। शिक्षा मंत्रालय। https://www.education.gov.in/
- नीति आयोग। (2022)। भारत नवाचार सूचकांक 2021। भारत सरकार। https://www.niti.gov.in/
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। (2023)। असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण: 2022–23। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

- स्टार्टअप इंडिया। (2021)। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना: दिशानिर्देश। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। https://www.startupindia.gov.in/
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)। (2023)। वार्षिक रिपोर्ट 2022–23। SIDBI। https://www.sidbi.in/
- ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर। (2023)। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2022/2023 ग्लोबल रिपोर्ट: एक नए सामान्य (न्यू नॉर्मल) के अनुरूप ढलना। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च एसोसिएशन। https://www.gemconsortium.ogr

THE RESEARCH DIALOGUE
Manifestation Of Perfection

THE RESEARCH DIALOGUE

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed & Refereed National Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-03, Issue-01, April-2024
www.theresearchdialogue.com
Certificate Number April-2024/36
Impact Factor (IIJIF-1.561)
Impact Factor (RPRI-4.73)

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

वेद प्रकाश दुबे

for publication of research paper title

"स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम एवं युवा रोजगार: चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ"

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed & Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-03, Issue-01, Month April, Year-2024.

Dr. Neeraj Yadav
Executive Chief Editor

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor-in-chief

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.theresearchdialogue.com

INDEXED BY